



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072020-220403  
CG-DL-E-07072020-220403

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2020/ आषाढ़ 16, 1942

No. 1977]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2020/ASHADHA 16, 1942

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ;

v f/ M p u k

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

**d kv k 2234 1/2**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1430(अ) तारीख 25 मार्च 2019, जो भारत के राजपत्र तारीख 26 मार्च 2019, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में “इरुगुर – देवनगुंथी पाइपलाइन परियोजना” के अन्तर्गत पेट्रोलियम परिवहन के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1430(अ) तारीख 25 मार्च 2019, की सूचना संबंधित भु-स्वामीयो को तारीख 10 जून, 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधिन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

v u q ३४

r ky d % v k ky j	ft y k&l y s		j kT; % r fey u kMq		
x be	l o ३ Q y kd @ l a %ky k% l d/2	l c & Mto & l a	{ k Q y		
			g ३ V s j	v k j s	ox ZehWj
1	2	3	4	5	6
पनीक्कानुर – 84	1	1	00	01	85

[फा. सं. आर.-11025(15)/6/2018-ओआर-1/ई/27006]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2020

**S.O. 2234(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O.1430 dated the 25<sup>th</sup> March, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 26<sup>th</sup> March, 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying a Pipeline “Irugur – Devangonthi” for the transportation of Petroleum Products in the state of Tamilnadu by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification vide S.O.1430 dated the 25<sup>th</sup> March, 2019, were made available to the concerned land owner by 10<sup>th</sup> June, 2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

### SCHEDULE

Taluk : Omalur	District:- Salem		State :- Tamil Nadu		
Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Panikkanur - 84	1	1	00	01	85

[F. No. R-11025(15)/6/2018-OR-I/E/27006]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND

MEENA